The Uttar Pradesh Sugarcane (Purti and Kharid Viniyman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970

Act 6 of 1971

Keyword(s):
Sugarcane, Purchase

Amendments appended: 2 of 1972, 10 of 1976, 34 of 1976, 17 of 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

128232

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 ई०, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में संशोधन सहित पारित किया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 को दुबारा पारित किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिये — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) यह 30 जून, 1970 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 में, खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 30 जून को समाप्त हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 15 जुलाई को समाप्त हो" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1970 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

Price .05 P.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 331 जनरल (लग०)—1971—1,834+50 S.S. (मे०) ।

L.A. 15/72.2
cop. 3

135682

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 जनवरी 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 1953 ई० की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(5) (क) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबंध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने के लिये सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 5 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों को फैक्ट्री के लिये चालू पेराई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से या उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके सम्बन्ध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) 'इकाई' या 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने अथवा उसके उत्पादन में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र-शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;"

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (5) में—

(1) शब्द "शक्कर उप-आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय;

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द " प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3-क के अनुसार वसूल होने योग्य कर की दशा को छोड़कर" रख दिये जायें।

(3) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई के स्वामी द्वारा अपील किये जाने की दशा में, शक्कर आयुक्त किसी ऐसी अपील को, जो उसके पास विचाराधीन हो, किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है, और किसी ऐसी अपील को वापस भी ले सकता है और उसका निस्तारण या तो स्वयं करेगा अथवा उसे किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है।"

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना और वर्तमान धारा 3-क को 3-कक के रूप में पुनः संख्यांकन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-क की संख्या बदलकर 3-कक कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 3-कक के पहले निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

फैक्टरी से शक्कर हटाने के पूर्व कर का भुगतान

"3-क(1)—किसी फैक्टरी का कोई स्वामी दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 को अथवा उसके पश्चात् जिसे आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है फैक्टरी में उत्पादित किसी शक्कर को, उपभोग के लिए अथवा बिक्री के लिए, या फैक्टरी के भीतर अथवा उसके बाहर कोई अन्य पदार्थ निर्मित करने के लिए तब तक न हटायेगा और न उसे हटवायेगा जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन लगाये गये कर का, जो, यथास्थिति, उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट धनराशि होगी, भुगतान न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शक्कर ऐसी किसी धनराशि का भुगतान किये बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी गोदाम अथवा अन्य संग्रह स्थान में जमा की जा सकती है, और जहां पर वह इस प्रकार जमा की जाय वहां से वह तब तक न हटायी जायगी जब तक कि उपयुक्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे फैक्ट्री में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर फैक्ट्री के स्वामी को दी गई किसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में, उस शक्कर की, किसी बैंक के पण्यमदार के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग में, उसके अनुप्रेरण पर बिक्री की दायिता पर कोई प्रभाव पड़ता है।

(2) प्रत्येक पेराई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र (और उक्त दिनांक को प्रारम्भ होने वाले पेराई के मौसम की दशा में इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र) कर निर्धारण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिए देय अस्थायी दर को पूर्ववर्ती पेराई के ऐसे मौसम के दौरान, जिसने फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा को फैक्टरी में उत्पादित शक्कर से सहसम्बद्ध करके निकालेगा और निर्दिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण 1:--यदि किसी ऐसी पूर्ववर्ती पेराई के मौसम के केवल किसी एक भाग में ही फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, तो पेराई के मौसम के उतने ही भाग पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा जिसके दौरान फैक्टरी में वस्तुतः उत्पादन किया गया ।

स्पष्टीकरण 2:--यदि फैक्टरी ने उस पेराई को मौसम के पूर्व, जिसके लिए अस्थायी कर निर्धारण किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ न किया हो, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी उसी क्षेत्र की अन्य फैक्टरियों से, यदि कोई हो, सम्बन्धित तुलनीय आधार-सामग्री अथवा किसी अन्य संगत कारण के आधार पर प्रति बोरी शक्कर के भुगतान की अस्थायी दर निर्दिष्ट कर सकता है ।

(3) पेराई के मौसम के अन्त में कर-निर्धारण प्राधिकारी, चालू पेराई के मौसम के दौरान फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा और फैक्टरी में उत्पादित शक्कर को ध्यान में रखकर शक्कर की प्रति बोरी के भुगतान के लिए पुनरीक्षित दर निकाल कर उसे निर्दिष्ट करेगा, और यदि ऐसे पुनरीक्षण पर दर घट या बढ़ जाय तो, यथास्थिति, अधिक या कम भुगतान की गयी धनराशि उक्त शक्कर के शेष स्टाक पर लगायी जायगी और शक्कर की प्रत्येक ऐसी शेष बोरी को हटाने के पूर्व दी जाने वाली धनराशि तदनुसार पुनः निश्चित की जायगी, और यदि स्टाक में ऐसी शक्कर न रहे तो स्वामी, यथास्थिति, धनराशि की वापसी पाने का हकदार होगा अथवा शेष धनराशि का भुगतान करेगा ।

(4) यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि उक्त शक्कर के स्टाक का कोई भाग हटा दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, और इस धारा के अधीन ऐसे भाग के प्रति देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसी कमी को उस सम्भव के स्टाक की शक्कर पर लगा कर वसूल किया जायगा ।

(5) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् क्रय किये गये गन्ने के विषय में धारा 3 के अधीन आरोपित कर के सम्बन्ध में :--

(क) धारा 3 की उपधारायें (2) तथा (3) लागू नहीं होंगी तथा कर गन्ने के क्रय के दिनांक को अथवा इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय समझा जायगा;

(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि जहां कर-निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि फैक्टरी के स्वामी ने इस धारा का उल्लंघन करके शक्कर को हटाया या हटवाया है अथवा फैक्टरी में उत्पादित या उपधारा (1) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके द्वारा जमा की हुई शक्कर का पूर्ण लेखा देने में असफल रहा है, तो कर का देनदार व्यक्ति हटाई गई या हटवाई गई अथवा लेखाविरत शक्कर की मात्रा के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि के अतिरिक्त इस प्रकार देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अग्रेतर धनराशि का शास्ति के रूप में देनदार होगा ;

(ग) इस धारा के उपबन्ध उस धारा के (उपर्युक्त परिष्कृत) उपधारा (4) तथा उपधारा (6), (7), (8), तथा (9) के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे; तथापि उस धारा की उपधारा (8) के अधीन प्रमाण-पत्र ऐसे आपवादिक एवं पर्याप्त कारणों के सिवाय जो अभिलिखित किये जायेंगे तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उस उपधारा में अभिदिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी की राय में खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई परिस्थिति विद्यमान है;

(घ) धारा (7) के उपबन्ध उसमें शक्कर आयुक्त के अभिदेशों के स्थान पर कर-निर्धारण प्राधिकारी के अभिदेशों को प्रतिस्थापित करते हुए लागू होंगे।"

धारा 3-ख का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3-ख में, शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय ।

धारा 4 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3-क) में शब्द " शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द " सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिये जायं ।

धारा 8 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी मात्रा में शक्कर हटाने अथवा हटवाने के लिये या" बढ़ा दिये जायें ।

धारा 15 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में—

(1) खण्ड (ङ) में सेमीकोलन के पश्चात् आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(च) फैक्टरी में या किसी अन्य संगृह स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियों का हटाना ;

(छ) धारा 3—क के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिये देय कर की धनराशि की गणना करने और देय कर के लिए इस प्रकार दी गयी धनराशि का समायोजन करने की रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये धारा 3—क में वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हों और उस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उपबन्ध आवश्यक समझे जायें; और," तथा

(3) वर्तमान खंड (च) को पुनाक्षरित खण्ड (झ) कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 20, 1971 का निरसन

10—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 36 जन० (लेग०)—1972—1799+50SS (मे०)।

153893

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 10 OF 1976]

[*Authoritative English Text to the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sansodhan) Adhiniyam,* 1976]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 24 of 1953.

2. In section 5 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(3) The Council shall consist of the following, namely :—

(i) two representatives of the sugar factory concerned, to be nominated by the occupier ;

(ii) five cane-growers from among persons, securing the first ten places in each of the preceding three annual sugarcane production competitions organised in the reserved area by the Cane Commissioner, to be elected by the members of the committees of management of the Cane Growers Co-operative Societies functioning in the reserve area according to the system of proportional representation by means of single transferable vote :

Provided that not less than two of the five cane-growers to be chosen shall be persons holding not more than two hectares area under sugarcane cultivation during the year in which the said competition was held ;

(iii) one representative of the licensed power-driven *khandsari* manufacturing units in the reserved area, to be elected by their owners ;

(iv) the District Cane Officer ;

(v) the Sugarcane Protection Inspector ;

(vi) one representative of the company registered under the Companies Act, 1956, known as the Regional Cane Development Corporation, to be nominated by it ;

(vii) the Senior Cane Development Inspector, who shall be *ex officio* Member-Secretary.

(3-A) The members of the Council shall elect from among themselves a person, not being a Government servant, to be the Chairman of such Council." ;

[For Statement of Objects and Reasons please see Uttar Pradesh *Gazette* (Extraordinary), dated March 27, 1976].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 31, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976).

(Recieved the Assent of the Governor on April 16, 1976 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary,* dated April 17, 1976).

PRICE 10 P

(*b*) in sub-section (4), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that the term of the first council to be constituted after the promulgation of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, shall be one year only."

Insertion of new section 8-A.

3. *After* section 8 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely--

Supersession of Council.

"8-A. If at any time, the State Government is, after taking into consideration the explanation, if any, of the Council, satisfied that the Council has made a wilful default in the performance of any of its functions and duties under this Act, it may, by notification, supersede the Council for such period as may be specified, and shall make such arrangements for the performance of the functions and duties of the Council, during the period of supersession, as it may deem fit."

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, by the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

यू0एस0यू0पी0—ए0 पी0 498 सा0 (विधा0)—25-2-77—4627—1976—1837+50 S S (मे०)।

154081 L.A. 15-176-34 Cat. 8

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 34 OF 1976]

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam*, 1976].

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976. Short title.

2. In section 2 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*j*-1), the following clause shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953.

"(*j*-2) 'Inspector' means any person appointed or any officer designated as inspector under section 11 ;"

3. *After* section 22 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :— Insertion of new sections 22-A and 22-B.

"22-A. Powers of certain officers to investigate into offences punishable under this Act. (1) An Inspector specially empowered in relation to cases generally or to any class of cases by the State Government, by notification, in that behalf, may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction.

(2) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

22-B. Duty of officers of certain departments to report offences and to assist Inspectors. Every officer of the Police, Revenue and Excise Departments shall be bound to give immediate information to an Inspector of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge and upon request made by an Inspector, to aid him in carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder."

विधान पुस्तका (राजकीय प्रकाश ...)

[For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated November 3, 1976].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 2, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 8, 1976.)

(Received the Assent of the Governor on November 16, 1976 under article 200 of the Constitution of India and was published in Part I(*a*) of the Legislative Supplement of the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated November 18, 1976).

Price 10 Paise

PSUP—A. P. 400 Sa. (Vidhayika)—29-12-76—3872—1976—1827+50 SS.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 17 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 24 of 1953

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, clause (b) shall be *omitted.*

Omission of sections 3 and 4

3. Sections 3 and 4 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 28

4. In section 28 of the principal Act, *for* the words "Board and Council" wherever occurring, the word "Council" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 3 and 4 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 provide respectively for the Constitution and the functions of the Sugarcane Board.

The functions of Sugarcane Board regarding replacement, development and region-wise classification of suitable and unsuitable sugarcane varieties, are being performed by a core committee constituted by the State Government. The Cane Commissioner, through bonding policy, imparts detailed direction pertaining to the sugarcane supply and purchase. The cane implementation committees constituted at the district level regularly monitor proportionate purchase of sugarcane and position of cane price payment during the crushing season. Since the functions of the Sugarcane Board are being performed by different committees, the existence of Sugarcane Board has become unnecessary. It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Act to omit the provisions relating to the Sugarcane Board.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 252 राजपत्र (हि0)–(386)–2006–597(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 38 सा० विधायी–(387)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

No. 1693(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)-17-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 23 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Act, 2008.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(a) after clause (i) the following clause shall be *inserted*, namely :–

(i-i) "Ethanol" means anhydrous ethyl alcohol of minimum 99 percentage strength, produced directly either from sugarcane juice or B-Heavy molasses or both.

Explanation :— When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice of B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every six hundred litres of ethanol so produced as equivalent to one ton production of sugar.

(b) *for* clause (j) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(j) 'Factory' means any premises including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working or on any day during the preceding twelve months and in any part of which any manufacturing process connected with the production of sugar by means of vaccum pan process or ethanol either directly from sugarcane juice or molasses, including B-Heavy molasses, or both as the case may be, is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power."

Amendment of section 17

3. In section 17 of the principal Act in sub-section (5), in clause (a) *for* the words "on the security of sugar" the words "on the security of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

Amendment of section 3-A of U.P. Act no. 9 of 1961

4. In section 3-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (1), in the first and second provisos for the word "sugar" wherever occurring the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (2) *for* the words "per bag of sugar" wherever occurring, the words "per bag of sugar or per sixty litres of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(c) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(3) At the end of crushing season or as the case may be, immediately after the closure of the factory for the crushing season the assessing authority shall workout and specify a revised rate of payment per bag of sugar or per 60 liters of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) by taking into account the quantity of sugarcane purchased for the factory and the sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) produced in the factory during the current crushing season, and where the rate is reduced or increased on such revision, the excess paid or the shortfall, as the case may be, shall be spread over the remaining stock of the said sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses), and the amount to be paid before removal of each such remaining bag of sugar or ethanol (directly produced form the sugarcane juice or B-Heavy molasses) be refixed accordingly, and if no such sugar or ethnol remains in stock then the owner shall be entitled to a refund or pay the balance, as the case may be."

(d) in sub-section (4) *for* the word "sugar" wherever occurring, the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

(e) in sub-section (5) *for* clause (b) the following clause shall be *substituted,* namely :–

"(b) sub-section (4) of that section shall apply with the modification that where the assessing authority is satisfied that the owner of a factory has removed or caused to be removed any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) in contravention of the provision of this section or has failed to account fully for the sugar produced or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses) in the factory or deposited by him under the first proviso to sub-section (1) the person liable to pay the tax shall in addition to the amount payable under sub-section (1) in respect of the quantity of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) so removed or unaccounted for, be also liable to pay by way of penalty a further sub not exceeding one hundred percent of the sub so payable."

Amendment of section 8

5. In section 8 of the principal Act, in the proviso *for* the words "any sugar" the words "any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several Countries of the world are successfully blending ethanol in Petrol. The Government of India has made 5% ethanol blending in petrol. During experiments and researches it has been proved that approximately 25% of ethanol can successfully be blended in petrol. With a view to increasing the availability of ethanol, the Government of India has amended the Cane (Control) Order, 1966 and thereby permitted the sugar factories to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh is a prominent State in producing sugarcane and sugar, even though several sugar factories could not make payment of cane price timely which makes cane growers aggressive. Under the above circumstances it has become necessary to permit the sugar factories of the State to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses to improve economic condition thereof so that they may become enable to make payment of cane price timely.

It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh Cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 to provide for authorising sugar factories in the State to produce ethanol directly from sugarcane Juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 476 राजपत्र (हि0)–(1051)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 107 सा विधायी–(1052)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

476 rph dATA 6